

ਦੇਵੀ ਜੀ

- 1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शारंग।
- 2.समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांक २ जनवरी, 2009

पू.सं.आ.सं.अनु-७

विषय— सम्यमान वेतनमान स्वीकृति की विसंगति का निराकरण ।

अहोदय

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा समय-समय पर समयमान वेतनमान के संबंध में निर्गत शासनादेशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी मांगलों में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेष्ठ/वैयक्तिक प्रोत्साहीय वेतनमान/समयमान वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अहं होने का पूर्व ही वास्तविक रूप से पदोन्नति हो जाता है, जबकि संवर्ग में उससे कनिष्ठ कार्मिक श्रेष्ठ/वैयक्तिक प्रोत्साहीय वेतनमान/समयमान वेतनमान अनुमन्य होने के पश्चात् वहाँ कतिपय मांगलों में उपर्युक्त के फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक से कम हो जाता है इस समस्या के निराकरण हेतु समय-समय पर निम्नलिखित प्रमाणित तथ्यें गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय निम्न व्याख्या करने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं—

“ऐसी मामले में जहाँ संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के लिए अर्ह होना के पूर्व ही पदोन्नत हो गया हो, जबकि कनिष्ठ कार्मिक सम्बन्धित पद पर सेलेक्शन ग्रेड अथवा सेलेक्शन ग्रेड तथा दृश्यितक प्रोन्नतीय वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान अनुमन्य होने के उपरान्त ऐसी वेतनमान प्राप्त किया हो, के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ के समान कर दिया जाय”

2-उपर्युक्त प्रस्तर-1 में की गई व्यवस्था का लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुगम्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की सेवा की परिस्थितियाँ समान एवं तुलनीय रही हों। साथ ही यदि वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को संलग्नता ग्रहण/वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/समयमान वेतनमान की अनुगम्यता की तिथि से अथवा सरकारी पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभ की अनुगम्यता हेतु अर्ह होता, ऐसे प्रकरण में सेवा पुस्तिका से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कार्मिक की प्रारम्भिक सेवा से तुलना करना अनिवार्य होगा कि वरिष्ठ गृहण की तिथि पर समान वेतनमान के समान सांगान पर वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम नहीं आये। यद्यपि वरिष्ठ के कार्यभार गृहण करने या अन्य सेवा छोड़ने से कनिष्ठ का प्राथमिक वेतन निर्धारण अधिक हो तब इसे समान स्थिति नहीं माना जा सकता।

3-उपयुक्त प्रस्तर-1/2 के अनुसार की गई व्यवस्था राज्य निधि से साव्यता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर नर्गचारियों पर भी सगान रूप से लागू होगी।

4-शासनादेश सं०-वे०आ०-2-560/दरा-45(एम)/99, दिनांक 02-12-2000 तथा उसके क्रम में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित राखे जावेंगे।

၁၆၆၆၂၄၆

(2011-2012)
 2011-2012

क्रमांक: (1)/xxvii(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।

सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।

सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

देशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।

3. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।

निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।

नार्ड फाईल।

आज्ञा री,

(सी0एन0 सिंह)
अपर सचिव।